



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, २० मई, २०२५

बैशाख ३०, १९४७ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—३

संख्या 497/2025 / ८-३०९९ / १७४३ / २०२० पार्ट—३

लखनऊ, २० मई, २०२५

अधिसूचना

प० आ०—८८

चूँकि, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम ५ के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या १८, सन् २०१६) की धारा ४ की उपधारा (४) के खंड (ख) के उपखंड (द) के अनुसरण में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को, स्वैच्छिक आधार पर, ऑनलाइन प्रणाली त्वरित एवं सरलीकृत विश्वास—आधारित योजना अनुमोदन प्रणाली (फास्टपास) पर रजिस्ट्रीकरण के दौरान, आवेदकों के अधिप्रमाणन के लिए हां/नहीं या/और ईकेवाईसी अधिप्रमाणन सुविधाओं का उपयोग करके आधार अधिप्रमाणन के संपादन के लिए, केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

अतएव अब, उपर्युक्त नियमावली के नियम ५ के अनुसरण में, राज्यपाल, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में भवनों/भूखंडों के मानविक्री की ऑनलाइन स्वीकृत के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हां/नहीं या/और ईकेवाईसी अधिप्रमाणन सुविधाओं का उपयोग करते हुए ऑनलाइन प्रणाली—त्वरित एवं सरलीकृत विश्वास आधारित योजना अनुमोदन प्रणाली (फास्टपास) पोर्टल— पर पंजीकरण के दौरान आवेदकों के प्रमाणीकरण के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, आधार अधिप्रमाणन के संपादन को अधिसूचित करते हैं।

(एक) आवेदकों का अधिप्रमाणन;

(दो) छद्म/प्रॉक्सी आवेदकों की रोकथाम।

2— आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिवार) अधिनियम, 2016 एवं तदीन बनाए गए नियमों और विनियमों तथा आधार अधिप्रमाणन के उपयोग के संबंध में विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करेगा।

3— यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
पी० गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 497/2025/VIII-3099/1743/2020 Part-3 dated May 20, 2025 :

No. 497/2025/VIII-3099/1743/2020 Part-3

Dated Lucknow, May 20, 2025

WHEREAS in pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) *read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020*, the Housing and Urban Planning Department, Uttar Pradesh, has been authorized by the Central Government for performance of Aadhaar authentication, on a voluntary basis, for authentication of applicants during registration on the online system- Fast and Simplified Trust-Based Plan Approval System- using Yes/No or/and eKYC authentication facilities;

NOW, THEREFORE, in pursuance of rule 5 of the aforesaid rules, the Governor is pleased to notify the performance of Aadhaar authentication, on a voluntary basis, for authentication of applicants during registration on the online system-Fast and Simplified Trust-Based Plan Approval System (FASTPAS) portal-using Yes/No or/and eKYC authentication facilities by the Housing and Urban Planning Department, Government of Uttar Pradesh for online sanctioning of maps of buildings/plots in the Uttar Pradesh Avas evam Vikas Parishad and development authorities of the Housing and Urban Planning Department Government of Uttar Pradesh for the following purposes:-

- i. authentication of applicants;
- ii. prevention of impersonation/proxy applicants.

2- Housing and Urban Planning Department, Government of Uttar Pradesh shall adhere to the relevant provisions of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, rules and regulations made thereunder and guidelines issued by the Unique Identification Authority, Government of India regarding the use of Aadhaar authentication.

3- This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order,
P. GURUPRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०य०पी०-५०पी० 49 राजपत्र (हिं०)-२-६-२०२५-(१५०)-५९९ प्रतियां-(डी०टी०पी०/ऑफसेट)।
पी०एस०य०पी०-५०पी० 2 सां आवास एवं शहरी नियोजन-२-६-२०२५-(१५१)-१३६५ प्रतियां-(डी०टी०पी०/ऑफसेट)।